

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2495]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 13, 2010/अग्रहायण 22, 1932

No. 2495]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 13, 2010/AGRAHAYANA 22, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2935(अ).—विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता में एक "विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा सं. 11011/58/2010-एन ई-III] सदा कान्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2010

S.O. 2935(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Ms. Justice Mukta Gupta, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam as Unlawful Association.

[F. No. 11011/58/2010-NE-III]

SADA KANT, Jt. Secy.